



प्रतापगढ़, राजस्थान में जनजातीय शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ विभाकर उपमन्यु¹

असिस्टेंट प्रोफेसर

विरायतन बी.एड. कॉलेज पावापुरी,
नालन्दा, बिहारडॉ रमेश कुमार राम²

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजशंकर कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन
कैमूर, बिहार

सारांश

शिक्षा समाज में बदलाव लाने, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और मानव संसाधन को विकसित करने का एक बहुत ज़रूरी साधन है। जब हम जनजातीय समुदायों की बात करते हैं, तो शिक्षा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ पढ़ना-लिखना सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, नौकरी के मौके, खुद पर भरोसा और विकास की प्रक्रियाओं में शामिल होने को भी बढ़ावा देती है। किसी भी समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा एक बुनियादी ताकत का काम करती है। यह एक व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, समझदारी और आत्मनिर्भरता पैदा करती है, और साथ ही समुदाय को सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से जोड़ती है। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए, शिक्षा विकास के अवसरों तक पहुँच बनाने का एक अहम ज़रिया है। इस अध्ययन का केंद्र राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है, जहाँ जनजातीय आबादी का अनुपात राज्य के दूसरे कई जिलों की तुलना में बहुत ज़्यादा है।

प्रमुख शब्दावली

शिक्षा, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक, जनजातीय, योजना एवं चुनौतियाँ।

प्रस्तावना

प्रतापगढ़ राजस्थान का एक जनजातीय बहुल जिला है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में कुल 8,67,848 लोग रहते थे। इनमें से अनुसूचित जनजाति की आबादी 5,50,427 थी - यानी पूरी जिले की आबादी का करीब 63.4 प्रतिशत। जनजातीय समुदाय में पुरुषों की गिनती 2,76,742 थी और महिलाओं की संख्या 2,73,685 रही। गाँवों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 5,45,422 थी, जबकि शहरों में यह आंकड़ा सिर्फ 5,005 था। इससे साफ पता चलता है कि प्रतापगढ़ की जनजातीय आबादी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही बसी हुई है। प्रतापगढ़ जिले की सामाजिक बनावट पर गौर करें तो जनजातीय शिक्षा का सवाल सिर्फ स्कूलों में नाम लिखवाने भर तक नहीं रुकता। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखना, प्राथमिक स्तर के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रखना और फिर उँची शिक्षा के साथ-साथ रोजगार देने वाली शिक्षा तक उनकी पहुँच बनाना - ये सब उतने ही ज़रूरी काम हैं।

प्रतापगढ़ की कुल साक्षरता दर 56.0 प्रतिशत आंकी गई, जो राजस्थान के 66.1 प्रतिशत के औसत से काफी पीछे थी। जिले में महिलाओं की साक्षरता दर 42.4 प्रतिशत रही, जबकि पुरुषों की साक्षरता 69.5 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में जनजातीय शिक्षा का विश्लेषण करते वक्त केवल साक्षरता के आंकड़ों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। शिक्षा में नामांकन, स्कूल में नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचने की क्षमता, तथा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे पहलुओं को भी उतना ही महत्व देना ज़रूरी है।

अध्ययन के उद्देश्य

➤ प्रतापगढ़ जिले में जनजातीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना तथा इस समुदाय में शैक्षिक स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक कारकों की पहचान करना।

- जनजातीय विद्यार्थियों के विद्यालयी नामांकन और शिक्षा में निरंतरता से जुड़ी समस्याओं का गहन विश्लेषण करना और ग्रामीण एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना।
- जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा में प्रमुख बाधाओं को समझने के साथ-साथ भाषा, शिक्षण विधियों और स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित शैक्षिक चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- जनजातीय शिक्षा के विकास में सरकारी योजनाओं और शैक्षिक हस्तक्षेपों की भूमिका को समझना तथा प्रतापगढ़ में जनजातीय शिक्षा को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

प्रतापगढ़ में जनजातीय शिक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

भौगोलिक एवं परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ

प्रतापगढ़ की जनजातीय जनसंख्या अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे हालात में, बच्चों को कई बस्तियों से विद्यालय तक पहुँचने के लिए अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों और बालिकाओं के लिए दूरी शिक्षा की निरंतरता में बाधा डाल सकती है। विद्यालयों की संख्या बढ़ाने से यह समस्या हल नहीं होगी; विद्यालयों का स्थान, सुरक्षित आवागमन, परिवहन सुविधाएं और छात्रावास व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक अवस्था

गरीबी जनजातीय शिक्षा की निरंतरता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। जब परिवार की आय सीमित होती है, तब बच्चों की शिक्षा पर होने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च परिवार पर अधिक बोझ डालता है। कई परिवारों में बच्चों का घरेलू काम, कृषि और अन्य आर्थिक कामों में सहयोग भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए केवल निःशुल्क शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। अन्य आवश्यकताओं, जैसे पाठ्य सामग्री, वर्दी, परिवहन, छात्रावास, छात्रवृत्ति, आदि के लिए भी धन की आवश्यकता होती है।

शिक्षक जागरूकता

शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों की पर्याप्त जानकारी न होने पर कुछ परिवार बच्चों की शिक्षा की अपेक्षा तत्काल आर्थिक सहयोग को अधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इसलिए स्कूल की निरंतरता प्रभावित होती है।

इस परिस्थिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, अभिभावक सलाह और समुदाय-आधारित जागरूकता कार्यक्रम लाभदायक हो सकते हैं।

शिक्षण और भाषा की समस्या

प्रारंभिक शिक्षा को जनजातीय विद्यार्थियों के लिए कठिन बना सकता है क्योंकि विद्यालय की भाषा और घर में बोली जाने वाली भाषा के बीच अंतर है। भारत में जनजातीय शिक्षा पर प्रकाशित साहित्य ने मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्रारंभिक शिक्षण से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया है। मूल स्रोत में भी भाषा को जनजातीय बच्चों की शिक्षा में एक बड़ी बाधा बताया गया है। प्रतापगढ़ में स्थानीय भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखकर द्विभाषी या बहुभाषी प्रारंभिक शिक्षण सामग्री बनाना लाभदायक होगा।

शिक्षकों की उपलब्धता और योग्यता

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। शिक्षक नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं है; उन्हें जनजातीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, स्थानीय परिस्थितियों को समझना चाहिए और विद्यार्थियों के साथ संवाद करना चाहिए।

जनजातीय क्षेत्रों में मुख्य मुद्दों में नियमित निगरानी की आवश्यकता और शिक्षक-संबंधी समस्याएं शामिल हैं।

बच्चों को शिक्षित करना

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा के सामने दूरी, घरेलू जिम्मेदारियाँ, सुरक्षा, आर्थिक सीमाएँ और माध्यमिक स्तर पर विद्यालय की उपलब्धता जैसे मुद्दे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए बालिकाओं के लिए सुरक्षित आवागमन, छात्रावास, छात्रवृत्ति और महिला शिक्षकों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

स्कूल छोड़ने की परेशानी

विद्यालय में प्रवेश ही जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा में पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाना और उच्च कक्षाओं तक पहुँचना वास्तविक चुनौती है। सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में जनजातीय विद्यार्थियों में विद्यालय छोड़ने की दर अधिक रही है। विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की ओर बढ़ने पर विद्यार्थियों की भागीदारी में कमी दिखाई देती है। प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय बहुल जिले में इस समस्या को सामाजिक,

आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। शिक्षा की निरंतरता प्रभावित हो सकती है अगर स्कूल घर से दूर हो, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो या बच्चे को घरेलू और आजीविका संबंधी कामों में सहयोग करना पड़े। घरेलू जिम्मेदारियाँ, सुरक्षा और माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता बालिकाओं के लिए अतिरिक्त चुनौती बन सकती हैं। विद्यालय छोड़ने की समस्या को दूर करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों की पहचान, नियमित उपस्थिति की निगरानी, अभिभावक संपर्क और आर्थिक और शैक्षिक सहायता को लागू करना चाहिए।

आवासीय शिक्षण संस्थाएं

आवासीय विद्यालयों की अवधारणा विशेष रूप से जनजातीय विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आवासीय स्कूल और छात्रावास दूरस्थ इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय तक पहुँच की भौगोलिक चुनौती को कम कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अधिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना और उच्च शिक्षा तक पहुँच विस्तारित करने की जरूरत बताई गई है। प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय बहुल जिले में ऐसी व्यवस्था विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और नियमित रूप से स्कूल जाने में मुश्किल पाते हैं।

स्थानीय भाषा का प्रशिक्षण व्यवस्था

भाषायी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पाठ्य-सामग्री बनाना शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ा सकता है। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है अगर विद्यार्थी की घरेलू भाषा और विद्यालय की भाषा में पर्याप्त समानता नहीं है। प्रतापगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय भाषायी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय, द्विभाषिक और सरल शिक्षण-सामग्री बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मूल स्रोत भी स्थानीय भाषा में अध्ययन सामग्री जनजातीय विद्यार्थियों को देने की सलाह देता है।

छात्रवृत्ति और सुविधाएँ

जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए, ताकि शिक्षा को आर्थिक कठिनाइयों से बाधित न किया जाए। विशेष रूप से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। ST विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सहायता बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है।

जनजातीय शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास और कार्यक्रम

भारत में लंबे समय से विभिन्न सरकारी प्रयासों ने जनजातीय समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक विकास की कोशिश की है। अध्ययन के अनुसार, जनजातीय विकास के लिए धन का प्रावधान पहली पंचवर्षीय योजना से किया गया था, जिससे जनजातीय विकास खंड और जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub-Plan) जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुईं। इनका लक्ष्य शोषण से जनजातीय समुदायों को बचाना और उनका सामाजिक-आर्थिक विकास करना था।

प्रतापगढ़ में जनजातीय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव

शिक्षा संस्थानों तक आसानी से पहुँच

दूरस्थ जनजातीय बस्तियों के विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुँचाने के लिए विद्यालयों का उचित स्थान, परिवहन सुविधाएँ और आवश्यकतानुसार छात्रावास व्यवस्था बनानी चाहिए।

बच्चों की सुविधाएँ

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए छात्रावास, सुरक्षित आवागमन, छात्रवृत्ति, स्वच्छ विद्यालयी सुविधाएँ और महिला शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए।

शिक्षा जागरूकता अभियान

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में निरंतर शैक्षिक जागरूकता और साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए। अभिभावकों को यह समझने की जरूरत है कि शिक्षा से दीर्घकालीन सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लाभ मिलता है, जो सिर्फ तत्कालीन रोजगार तक सीमित नहीं है। मूल स्रोत भी जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान को प्राथमिकता देने की सलाह देता है।

स्थानीय समुदाय का सहयोग

सरकारी तंत्र जनजातीय शिक्षा को सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। विद्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम समुदाय और अभिभावकों के बीच नियमित चर्चा होनी चाहिए। इससे समुदाय में शिक्षा पर नियंत्रण की भावना पैदा होगी।

शिक्षण देखरेख का प्रभाव बढ़ाना

समय-समय पर विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए। विभागीय समन्वय को मजबूत करने से स्कूलों में वास्तविक समस्याओं की पहचान और उनका समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। मूल अध्ययन ने भी नियमित निरीक्षण और उचित निरीक्षण की जरूरत पर बल दिया है।

स्थानीय गुरुओं की नियुक्ति

जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय भाषा, समाज और सांस्कृतिक परिस्थितियों से परिचित शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मूल अध्ययन में भी जनजातीय और महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया गया है।

निष्कर्ष

जनजातीय शिक्षा का विकास प्रतापगढ़, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जनजातीय बहुल जिला, के सामाजिक और आर्थिक विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। 2011 की नवीनतम पूर्ण आधिकारिक जनगणना के आंकड़े दिखाते हैं कि जिले में एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ऐसी जनसंख्या संरचना को देखते हुए, जनजातीय विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जनजातीय शिक्षा की समस्या केवल विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थियों को जोड़े रखना, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्थिक कठिनाइयों को कम करना और स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था बनाना भी समान महत्वपूर्ण है। भाषा, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक दूरी, अभिभावकीय दृष्टिकोण, शिक्षक-संबंधी समस्याओं और निगरानी को मूल अध्ययन में भी महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में दिखाया गया है।

प्रतापगढ़ में जनजातीय शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा नीति का आधार “पहुँच + गुणवत्ता + निरंतरता + समानता” होना चाहिए। जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों को व्यापक बनाने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक और प्रभावी प्रशासनिक निगरानी की आवश्यकता होती है।

जनजातीय शिक्षा को समावेशी विकास, समान अवसर और सामाजिक न्याय की आधारभूत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल कल्याणकारी कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में जनजातीय विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देने वाली शिक्षा व्यवस्था बनाने की जरूरत है।

सन्दर्भ - सूची

1. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार। *भारत की जनगणना 2011 : जिला जनगणना पुस्तिका—प्रतापगढ़, राजस्थान*। नई दिल्ली : भारत सरकार।
2. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार। *प्राथमिक जनगणना सारणी 2011 : राजस्थान में अनुसूचित जनजाति—प्रतापगढ़ जिला*। नई दिल्ली : भारत सरकार।
3. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार। *अनुसूचित जनजातियों के लिए लिंगवार शैक्षिक स्तर (C-08), जनगणना 2011*। नई दिल्ली : भारत सरकार।
4. साहू, कबिता कुमारी (2014)। “भारत में जनजातीय शिक्षा की चुनौतीपूर्ण समस्याएँ।” *आईओएसआर जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस*, खंड 3, अंक 2, पृ. 48–52। *Challenging_Issues_of_Tribal_Education_i.pdf*
5. सुजाता, के. (2002)। “अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा।” गोविंदा, आर. (सम्पा.), भारत शिक्षा रिपोर्ट : बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा। नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। *Challenging_Issues_of_Tribal_Education_i.pdf*

6. सेडवाल, एम. एवं कामत, संगीता (2008)। प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में शिक्षा एवं सामाजिक समानता। नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। *Challenging_Issues_of_Tribal_Education_i.pdf*
7. लाल, एम. (2005)। समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए समावेशी विकास की रणनीति के रूप में शिक्षा। *Challenging_Issues_of_Tribal_Education_i.pdf*
8. अब्दुल रहीम, ए. (2011)। “भारत में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा : एक मूल्यांकन।” *इकोनॉमिक अफेयर्स*, खंड 56, अंक 2, पृ. 233–242।